जवाहरात के निर्यात का संवर्धन

1024. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज और धातु व्यापार निगम ने घरेलू स्वर्णकारों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दर पर स्वर्ण उपलब्ध करा कर हीरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनायी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और उस योजना को अभी तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वर्णाभूषणों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निगम में भारत का हिस्सा बहुत कम है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विदेशों में भारतीय स्वर्णाभूषणों की भारी मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो स्वर्णाभूषणों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय व्यापार का वर्तमान हिस्सा कितना है तथा इसमें वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए क्या योजनाएं बनायी गयी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम०एम० टी०सी०) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख कल्लेक्सों और निर्यात संसाधन जोनों में आभूषण एककों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दरों पर सोने की आपूर्ति कर रहा है । एम०एम०टी० सी० ने इसी स्रोत से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी०टी०ए०) को सोने की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र के निर्यातकों को स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण तथा आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अध्याय 21, खंड 2 में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन एवं प्रतिपूर्ति के तहत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर सोने की आपूर्ति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है

(ग) ऐसा अनुमान है कि स्वर्णाभूषणों का विश्व बाजार लगभग 100,000 करोड़ रुपए का है जबकि वर्ष 1990-91 में भारत के निर्यात लगभग 364 करोड़ रुपए के थे ।

(घ) और (ङ) इस समय विदेशों में परम्परागत स्वर्णाभूषण की मांग बहुत अधिक नहीं है । तथापि, स्वर्णाभूषण को निर्यात के लिए थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात कर लिया गया है । चालू वर्ष के लिए स्वर्णभूषण का लक्ष्य 500.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है । स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को निरस्त करना और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर स्वर्ण उपलब्ध कराने के लिए नीतियां तैयार करना, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख आभूषण कंप्लेक्स स्थापित करना निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं ।

1025. (Transferred to the 9th Deccember, 1991)

1026. (Transferred to the 9th December, 1991)

Foreign investment in India

1027. MISS. SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) Whether the European Commission Vice-President has said that if India wanted to attract foreign investment it should guarantee protection to high technology and accept the Western concept on Trade Related Intellectual Property Rights, as per the news item entitled "Protect Patents to boost Trade E. C." which appeared in the Times of India of the 30th October, 1991; and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) During the visit of Mr. Andriessen,

Vice President of the European Commission to India from 26 to 28 October 1991, he expressed the view that if there was inadequate protection for intellectual property rights, foreign investment in India would be affected.

(b) Government does not agree with this view. India will be able to attract foreign direct investment as a result of the measures taken recently. India's intellectual property regime compares favourably with that of other developing countries and even with that of many industrialised countries. However, it is primarily in the area of patents that the Indian law differs from that of other countries. This is on account of our concerns regarding food security and access to health care and medicines at affordable prices.

Promotion of Production and Export of Tea

1028. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are taking any steps to increase production of tea; and

(b) if so, the various efforts made in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Measures taken by the Government to increase production of tea include:

(i) Short term measures such as promoting optimisation of inputs and improved cultural practices.

(ii) Medium term measures such as promoting irrigation, drainage, rejuvenation, pruning and infilling.

(iii) Long-term measures such as promoting extension planting and replanting.

In this direction, the Tea Board operates a number of schemes such as Tea Plantation Finance Scheme, Tea Machinery and Irrigation Equipment Hire Purchase Scheme, Tea Area Rejuvenation and Consolidation Scheme, New Tea Unit Financing Scheme for non-traditional areas. Darjeeling Interest Subsidy Scheme Interest subsidy on Bank loan for irrigation and drainage Interest subsidy scheme on bank loan for extension planting, and Special Subsidy Scheme for conversion of vegetable land in tea cultivation in the Nilgiris District of Tamil Nadu.

Amount of Exports in Dollar

1029. SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the actual amount of total export in terms of dollar, month-wise during the last three years till the end of 31st October, 1991; and

(b) what is the percentage of growth in this regard as achieved during each quarter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) INDIA's EXPORT BY MONTH: 1988-89 TO APRIL-SEPT. 1991-92.

(Value US $ Million)

Period	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
April	1094	1246	1424	1488
May	1101	1283	1509	1292
June	998	1200	1328	1225